नीति आयोग रिपोर्ट : नई संभावनाओं पर जोर

एआइ से जीडीपी 10 साल में बढ़ सकती है 600 अरब डॉलर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) को लेकर लंबे समय से यह धारणा रही है कि यह मानव नौकरियों को सीमित कर देगा और रोजगार के अवसरों में कटौती होगी। लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट इस सोच से अलग तस्वीर पेश करती है। सोमवार को जारी रिपोर्ट 'विकसित भारत के लिए एआइः त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए अवसर' के मुताबिक, भारत में विभिन्न उद्योगों में एआइ को तेजी से अपनाए जाने से 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 500 से 600 अरब डॉलर तक की वृद्धि संभव है। वैश्विक स्तर पर भी आने वाले दशक में एआइ के इस्तेमाल से 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास विशाल एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) कार्यबल, तेजी से बढ़ता आरएंडडी इकोसिस्टम और मजबूत डिजिटल क्षमताएं हैं, जिनसे वह वैश्विक एआइ इकोनॉमी का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर सकता है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रह्मण्यम ने रिपोर्ट लॉन्च करते हुए कहा कि एआइ केवल उत्पादकता और नवाचार को नया आयाम ही नहीं देगा, बल्कि भारत में रोजगार भी बढ़ाएगा। उनके अनुसार, 2035 तक एआइ से भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान संभव है।

किन क्षेत्रों में होगा सबसे ज्यादा असर?

रिपोर्ट के मुताबिक, एआइ का सबसे बड़ा प्रभाव वित्तीय सेवाओं व विनिर्माण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अनुमान है कि इनके माध्यम से जीडीपी में एआइ का योगदान 20 से 25 प्रतिशत तक हो सकता है। वित्तीय सेवाओं में 50 से 55 अरब डॉलर और विनिर्माण में 85 से 100 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त प्रोडक्टिविटी जुड़ने की संभावना है।